प्रदेश व्यापी धान और मक्का खरीदी का विशेष अभियान शुरू

रायपुर, (आरएनएस)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य से शुरू हो रहे धान और मक्का खरीदी के विशेष अभियान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉ. सिंह ने आज यहां जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि सहकारी समितियों के सहयोग से किसानों के हित में चलने वाला यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लम्बा प्रदेश व्यापी अभियान है। धान बेचने के लिए सहकारी समितियों में पंद्रह लाख 79 हजार किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। यह संख्या पिछले साल की तुलना में एक लाख 27 हजार ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कहा-समर्थन मूल्य नीति के तहत धान खरीदी 31 जनवरी 2018 तक और मक्के की खरीदी 31 मई 2018 तक चलेगी। इसके लिए राज्य की एक हजार 333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और वृहताकार बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (लैम्प्स) के कार्य क्षेत्रों में 1992 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से इस अभियान का लाभ उठाने और अपनी उपज का वाजिब मूल्य प्राप्त करने के लिए धान और मक्का निकटवर्ती खरीदी केन्द्रों (उपार्जन केन्द्रों) में बेचने की अपील की है। उन्होंने किसानों के नाम अपने संदेश में कहा है -किसान भाई-बहनों को धान बेचने के लिए अपने गांव से ज्यादा दूर न जाना पड़े इसके लिए राज्य सरकार ने औसतन प्रत्येक साढ़े पांच ग्राम पंचायतों के बीच एक धान खरीदी केन्द्र की स्थापना की है। जिला कलेक्टरों और अन्य संबंधित अधिकारियों को उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। खरीदी और भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था की गई है। जिस दिन किसान धान बेचेंगे, उनकी राशि उसी दिन उनके बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कर दी जाएगी। डॉ. रमन सिंह ने कहा-इस वर्ष धान के समर्थन मूल्य में 80 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके फलस्वरूप कॉमन अथवा मोटा धान 1550 रूपए और ए-ग्रेड अथवा पतला धान 1590 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। मक्के की खरीदी में भी 60 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसान निर्धारित उपार्जन केन्द्रों में मक्का 1425 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों को वर्ष 2016 के धान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 2100 करोड़ रूपए का बोनस दिया है। किसान इस वर्ष जो धान बेचेंगे, उन्हें उसका बोनस अगले साल दिया जाएगा। इसकी भी तैयारी चल रही है। प्रदेश के सभी 27 जिलों में समितियों के माध्यम से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा और मक्के की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाएगी।

नवोदय विद्यालय में युवा उत्सव के दौरान आकर्षक कार्यक्रम

महासमुंद (आरएनएस)। .सरायपाली में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विगत दिनों जवाहर नवोदय विद्यालय में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. रमाकांत बाजपेयी, बिहारीलाल अग्रवाल, चंद्रकुमार पटेल, मुरलीधर एवं नवोदय के प्राचार्य वायएसएस चंद्रशेखर की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सहित्यिक व शास्त्रीय गीत, संगीत के विभिन्न विधाओं की आकर्षक प्रस्तुतियां प्रतिभागियों द्वारा दी गई। इसमें झांझर, मांदर बाजे लोकगीत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। एकल शास्त्रीय गायन में राग यमन के लिए खुशबू चौहान, तात्कालिक भाषण के लिए योगेश भोई को प्रथम स्थान मिला। मुख्य अतिथि डॉ. बाजपेयी ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की सराहना करते हुए, लोक संस्कृति को कायम रखने की बात कही। प्राचार्य ने ब्लॉक स्तर पर प्रथम आने वाले कलाकारों को राज्य स्तर पर भी सफलता प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगीत शिक्षक डीएन कोहाड़, कला शिक्षक एसके वर्मा, हेमसागर कैवर्त, बीबी कर एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा।

विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

कोरबा (आरएनएस)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा श्री राकेश बिहारी घोरे, के निर्देशानुसार नालसा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दस दिवसीय राष्ट्रीय अभियान कनेक्टिंग टू सर्व के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पी.डब्ल्यू.डी. रामपुर कोरबा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें श्रीमती हिमाशूं जैन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा सभी छात्रा-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन किये जाने, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विभिन्न न्यायालयों की संक्षिप्त जानकारी, किस प्रकरण का कहाँ अपील किया जाना है के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कु. सीमा जगदल्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा महिलाओं के अधिकार, नि:शुल्क विधिक सेवा अधिनियम के अंतर्गत तहसील स्तर पर वरिष्ठ न्यायाधीश/अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय स्तर पर, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय स्तर, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को जो विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य एवं शिक्षकगण उपस्थित थे

ताज के आसपास लगा है निर्माण कार्यो पर प्रतिबन्ध

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह ताज महल और ताज ट्रेपिजियम जोन (टीटीजेड) के भीतर और इर्दगिर्द सतत विकास सुनिश्चित करने और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर 'पूरी तरह प्रतिबद्ध' है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामे में कहा गया है कि टीटीजेड 10,400 वर्गकिमी का इलाका है जो उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और इटावा जिलों तथा राजस्थान के भरतपुर जिले तक फैला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह एक अलग सूक्ष्म स्तरीय योजना पर विचार कर रही है जो ताजमहल की उचित सुरक्षा एवं संरक्षण तक सीमित होगी। शीर्ष अदालत में पेश हलफ नामे में राज्य सरकार ने कहा कि ताज महल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रावधानों को आगरा के मास्टर प्लान - 2021 में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा , '' ससम्मान यह बताया जाता है कि राज्य खासतौर से ताज ट्रेपिजियम जोन के भीतर और इर्दगिर्द पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य वादा करता है कि वह पर्यावरण संबंधी कानूनों और इस अदालत के सभी आदेशों का पूरी तरह से पालन कर ताज ट्रेपिजियम जोन में पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन सुनिश्चित करेगा।' राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष इस मामले को रखा और हलफनामा पेश करने की इजाजत मांगी। पीठ ने राज्य को हलफनामा पेश करने की इजाजत दे दी। इसे शीर्ष अदालत के 27 अक्तूबर के उस आदेश का अनुपालन करते हुए जमा किया गया है जिसमें ताज महल और टीटीजेड के संरक्षण पर विस्तृत नीति पेश करने को कहा गया।

प्रदेश में हादसे के बाद हुई हिंसा में सबसे ज्यादा मौतें

कोलकाता (आरएनएस)। भारत में हादसे के बाद कई बार हिंसा हो जाती है और इसमें लोग मारे जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद हुई हिंसा के दौरान मौत के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। वर्ष 2016 में राज्य में इस तरह की मौतों के 208 मामले सामने आए, वहीं 229 लोग घायल हो गए। हालांकि यह अभी शुरुआती रिपोर्ट है और फाइनल रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट संसद को सौंपी जाएगी। वर्ष 2015 में ओडिशा इस तरह की मौतों के मामले में शीर्ष स्थान पर था। यहां इस तरह की 2239 घटनाओं में 800 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2015 में 252 मौतें हुई थीं और यह दूसरे स्थान पर रहा था। विशेषज्ञों के मुताबिक हालांकि यह संख्या कम हुई है लेकिन यह ट्रेंड राज्य के लिए ठीक नहीं है। यह पुलिस तथा कानून और व्यवस्था में अविश्वास का प्रतीक हो सकता है। प्रख्यात समाज शास्त्री प्रशांत रॉय ने कहा, यह स्पष्ट है कि लोग कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, उन्हें शायद यह भी नहीं पता होता है कि घायल कौन है। पुलिस समय पर नहीं पहुंच रही है, यह भी एक कारण हो सकता है। एक राज्य ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने के मामले बहुत कम हैं। तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में सड़क हादसों में लोगों की मौत का संख्या ज्यादा है लेकिन हिंसा में मौतों की संख्या कम है।

वहीं एक रिटायर पुलिस अधिकारी का मानना है कि यह पूरी तरह से कानून और व्यवस्था के फेल होने का मामला है। शीर्ष अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

तालिबान के हमले में 22 पुलिसकर्मी मारे गए

काबुल , (आरएनएस)। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी कंधार प्रांत में तालिबानी लड़ाके रातभर में करीब 15 सुरक्षा चौकियों में घुस गए और कुल 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। कार्यकारी प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मतीउल्लाह हेलाल ने कहा कि सोमवार रात को विद्रोही सुरक्षा चौकियों में घुस गए। इस घटना में कम से कम 15 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। हेलाल ने कहा कि ये हमले मेवांद और जहेरी जिलों में हुए और कुछ मुठभेड़ घंटों तक चली। उन्होंने कहा कि 45 तालिबानी मारे गए और 35 अन्य जख्मी हो गए। क्षेत्र से संसद के सदस्य खालीद पश्तून ने बताया कि 37 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 30 अन्य जख्मी हुए हैं। तालिबान की ओर से तुरंत कोई टिप्पणी नहीं मिली है। तालिबान ने अफगान सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ा दिए हैं।

कंप्यूटर नेटवर्को पर है उत्तर कोरिया के मालवेयर की नजर

वॉशिंगटन, (आरएनएस)। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर कोरिया में विकसित मालवेयर (कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर) की अभी भी कई कंप्यूटर नेटवर्को पर नजर है। हैकर सरकार, वित्तीय संस्थानों, मीडिया संगठनों और ऑटोमोटिव संस्थानों तक पहुंच बना सकते हैं। गृह सुरक्षा विभाग द्वारा जारी एक अलर्ट में तथाकथित हैकर समूह हिडन कोबरा की गुप्त गतिविधियों के प्रति चेतावनी दी गई है। इस समूह को लेजारस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने वर्ष 2009 से हुए कई साइबर हमलों के पीछे इस समूह को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि यह समूह उत्तर कोरियाई सरकार से जुड़ा हुआ है। हालांकि उत्तर कोरिया ने किसी भी तरह के साइबर हमले की योजना से इनकार किया था। मंगलवार को जारी की गई चेतावनी में गृह सुरक्षा विभाग की डीएचएस कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पॉन्स टीम (सीईआरटी) ने कहा कि नेटवर्क के और अधिक दुरुपयोग के लक्ष्य से हैकर अभी भी शिकार हुए कंप्यूटर नेटवर्को में घात लगाए हुए हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ नेटवर्क में वोल्मार के बैकडोर ट्रोजन अभी भी मौजूद हो सकते हैं जो हैकर को दूर से ही किसी भी सिस्टम को पूरी तरह नियंत्रित करने का मौका दे सकते हैं।

सेना ने तख्तापलट की कोशिशों को बताया गलत

हरारे, (आरएनएस)। जिम्बाब्वे में बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रीय प्रसारक 'जेडबीसी' के मुख्यालय पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया है. '' ने बुधवार को बताया, राजधानी हरारे में विस्फोट की खबरें भी मिलीं हैं लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं है। वहीं, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में देश के राजदूत ने तख्तापलट की खबरों को खारिज कर दिया था। जिम्बाब्वे की सत्तारूढ़ पार्टी ने देश के सेना प्रमुख द्वारा संभावित सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी देने के बाद राजद्रोह करने का आरोप लगाया था। जनरल कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा ने राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे द्वारा उप राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के बाद चुनौती दी थी। वहीं, तनाव मंगलवार से बढ़ा है जब बख्तरबंद वाहन हरारे के बाहर की सड़कों पर तैनात कर दिए गए थे और इनका यहां तैनात होने का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं था।एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे के शासन की महत्वपूर्ण समर्थक रही सेना और 93 वर्षीय नेता के बीच तनाव गहरा गया है और बुधवार तड़के बोरोडाले में लंबे समय तक गोलीबारी हुई। मुगाबे की जेडएनयू-पीएफ पार्टी ने सेना प्रमुख जनरल कांस्टैनटिनो चिवेंगा पर मंगलवार को 'राजद्रोह संबंधी आचरण' का आरोप लगाया। इस विवाद ने मुगाबे के लिए, ऐसे समय में बड़ी परीक्षा की घड़ी पैदा कर दी है, जब पहले कह वहां हालात खराब चल रहे हैं। चिवेंगा ने मांग की है कि मुगाबे उपराष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा की पिछले सप्ताह की गई बर्खास्तगी को वापस लें। जेडएनयू-पीएफ ने कहा कि चिवेंगा का रुख 'स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शांति को बाधित करने वाला है और यह उनकी ओर से राजद्रोह संबंधी आचरण की ओर इशारा करता है क्योंकि इसका मकसद विद्रोह को भड़काना है।' मनांगाग्वा को बर्खास्त किए जाने से पहले उनका मुगाबे की पत्नी ग्रेस (52) से कई बार टकराव हुआ था। ग्रेस को अगले राष्ट्रपति के लिए, मनांगाग्वा का प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है।

सऊदी अरब में योग को मिला खेल का दर्जा

रियाद , (आरएनएस)। भारत में जहां योग और धर्म लेकर विवाद छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर इस्लामिक देश सऊदी अरब में योग को एक खेल के तौर पर आधिकारिक मान्यता मिल गई है। सऊदी अरब की ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज के तौर योग सिखाने को आधिकारिक मान्यता दे दी है। सऊदी अरब में अब लाइसेंस लेकर योग सिखाया जा सकेगा। खास बात यह है कि नोफ मारवाई नामक एक महिला को सऊदी अरब की पहली योग प्रशिक्षक का दर्जा भी मिल गया है। योग को खेल के तौर पर सऊदी में मान्यता दिलाने का श्रेय भी नोफ को ही जाता है। नोफ ने इसके लिए लंबे समय तक अभियान चलाया था। अरब योगा फाउंडेशन की फाउंडर नोफ का मानना है कि योग और धर्म के बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक तौर पर स्वीकृति मिली थी और 21 जून को हर साल विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है।

दो छात्रों ने दी एनएएस परीक्षा

श्रीनगर (आरएनएस)। सुदूरवर्ती प्राथमिक विद्यालय जोगडी के कक्षा पांच के दो छात्रों को भी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसे इस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि भी बताते हुए कहा कि ऐसी परीक्षाओं में चयनित होने से शैक्षणिक स्तर में और ज्यादा गुणात्मक सुधार भी आएगा। जोगडी की ग्राम प्रधान सीता देवी ने कहा कि जोगडी जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के स्कूल के छात्रों राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा में शामिल होना स्वयं में एक उपलब्धि भी है। सरकारी स्कूलों में प्रारंभ से ही अंग्रेजी विषय भी लागू हो जाने से शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आ रहा है। शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष ताजबर सिंह रावत ने इसे विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए विशेष अवसर और उपलब्धि बताया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जयश्री जोशी और अध्यापक आनंद सिंह पंवार ने कहा कि अभिभावकों के सहयोग से शिक्षण कार्य में निरंतर और गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले केजरीवाल

चंडीगढ़, (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सीएम अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच बुधवार को चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। राजधानी में जहरीले स्मॉग के कारण केजरीवाल पिछले कुछ समय से खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने की इच्छा जता रहे थे। हालांकि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल से मुलाकात से साफ इनकार कर दिया था। समझा जाता है कि खट्टर और केजरीवाल के बीच मुलाकात में किसानों द्वारा पराली जलाने के मुद्दे और प्रदूषण कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल ने 8 नवंबर को हरियाणा के सीएम को पत्र लिखा था। शुरुआत में तो सीएम खट्टर ने भी केजरीवाल से यह कहते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया था कि उनकी सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से ही उचित कदम उठा रही है। बाद में स्मॉग के मुद्दे पर एनजीटी की केंद्र सरकार, पड़ोसी राज्यों और दिल्ली सरकार को फटकार लगाने के बाद हरियाणा सीएम ने केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे मिलने को तैयार होने की बात कही थी। केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा के सीएम ने उन्हें फोन किया और कहा था कि वह मंगलवार तक दिल्ली में हैं, लेकिन बहुत व्यस्त होने के कारण दिल्ली में मीटिंग नहीं हो सकती। केजरीवाल ने कहा था कि वह बुधवार को इस मीटिंग के लिए चंडीगढ़ जाएंगे।

मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है पर राम जन्मभूमि नहीं: स्वामी

नई दिल्ली, (आरएनएस)। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुई सुलह की कोशिशों के बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है पर राम जन्मभूमि पर नहीं। स्वामी ने कहा, मस्जिद तो कहीं भी बनाई जा सकती है, यहां नमाज पढ़ा जाता है। सऊदी अरब में मस्जिदों को तोड़ा गया है और शिफ्ट भी किया गया है। उसी प्रकार से भारत में भी बाबरी मस्जिद को आंबेडकर नगर जिले की सीमा पर शिफ्ट किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। उन्होंने आगे कहा, यहां 40 हजार मंदिरों को तोड़ा गया। हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं। हम केवल तीन की बात कह रहे हैं- मथुरा में कृष्ण का, अयोध्या में राम का और वाराणसी में काशीविश्वनाथ का मंदिर। गौरतलब है कि ताजा घटनाक्रम के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर अयोध्या जाने वाले हैं। 16 नवंबर को वह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सभी पक्षकारों से बात करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि इस विवाद को कोर्ट के बाहर बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। लंबे समय से अटके इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। यह तारीख काफी मायने रखती है क्योंकि एक दिन बाद ही विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना को 25 साल पूरे हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर ने 1528 में कराया था। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि वहां पहले भगवान राम का भव्य मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया।

11 करोड़ में नीलाम हुई दाऊद की प्रॉपर्टी

मुंबई (आरएनएस)। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई में मौजूद संपत्तियों की नीलामी हो गई है। दाऊद की संपत्तियों को सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने करीब 11 करोड़ रुपये में खरीद लिया है, जिसमें रौनक अफरोज होटल, शबनम गेस्ट हाउस और डांबरवाला इमारत शामिल है। इन तीनों के अलावा औरंगाबाद फैक्ट्री, मजगांव फ्लैट, दादरीवाला चॉल की नीलामी भी हो गई। इस नीलामी में रौनक अफरोज होटल 4 करोड़ में बिका, वहीं शबनम गेस्ट हाउस तथा डांबरवाला इमारत के 5 कमरों की भी नीलामी हो गई। यह नीलामी चर्चगेट स्थित आईएमसी बिल्डिंग में सुबह 10 बजे शुरू हुई। नीलामी का आयोजन स्मगलर ऐंड फॉरेन एक्सचेंज मैनीपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट साफीमा के तहत हुआ। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग ने विज्ञापन के जरिए नीलामी की जानकारी दी थी। राजस्व विभाग ने 14 नवंबर को होने वाली इस नीलामी के लिए बंद लिफाफे में निविदाएं मांगी थीं। इनमें से हर संपत्ति की आरक्षित कीमत एक से डेढ़ करोड़ रुपये के बीच रखी गई थी। इस तरह इनका कुल आधार मूल्य करीब 5 से साढ़े 5 करोड़ रुपये था। नीलामी में शामिल होने वालों को 10 नवंबर तक अपना ब्योरा एसएएफईएमए या एनडीपीएसए विभाग को देना था। इस नीलामी की निविदा प्रक्रिया 10 नवंबर को समाप्त हुई थी। सूत्रों के मुताबिक नीलामी के लिए देश भर के करीब 10 निवेशकों ने आवेदन किया था, जिसमें सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट भी शामिल था। पहले भी हुई होटल की नीलामी होटल रौनक अफरोज की नीलामी साल 2015 में भी हुई थी, तब पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन ने 30 लाख डिपॉजिट भरने के बाद ऊंची बोली लगाकर नीलामी अपने नाम की थी। लेकिन, 3.98 करोड़ की बकाया रकम नहीं भर पाने की वजह से नीलामी रद्द हो गई थी।